जनसत्ता

7 दिसंबर, 2019

यथावत मुद्रा

माना जा रहा था कि आर्थिक विकास दर के नीचे की तरफ रुख होने के आंकड़े आने के बाद बाजार में पूंजी का प्रवाह बढ़ाने के मकसद से रिजर्व बैंक अपनी दरों में कुछ कटौती करेगा। मगर उसने ऐसा न करने का फैसला किया। इससे पहले वह पांच बार रेपो रेट में कुल मिला कर 1.35 फीसद की कटौती कर चुका है। इस मौद्रिक समीक्षा में रिजर्व बैंक ने कहा कि बार-बार बैंक दरों में कटौती करना उचित नहीं है। फिलहाल उन खामियों को दूर करने की जरूरत है, जिनकी वजह से आर्थिक वृद्धि दर बाधित हो रही है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने अपना आर्थिक विकास दर का अनुमान घटा कर पांच फीसद कर दिया है। पिछली तिमाही में उसने विकास दर 6.1 फीसद रहने का अनुमान लगाया था, पर दूसरी तिमाही के दौरान विकास दर घट कर साढ़े चार फीसद पर पहुंच गई। इसके अलावा खुदरा मुद्रास्फीति यानी महंगाई की दर बढ़ कर 4.6 फीसद तक पहुंच गई है। इन स्थितियों को देखते हुए रिजर्व बैंक ने अपनी मुट्ठी बंद रखना जरूरी समझा है। इस तरह ताजा मौद्रिक समीक्षा के बाद सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

विकास दर की रफ्तार सुस्त होने के आंकड़े काफी पहले से आने शुरू हो गए थे, मगर उन्हें गंभीरता से लेते हुए व्यावहारिक कदम उठाने के बजाय सरकार अर्थव्यवस्था की गुलाबी तस्वीर पेश करती रही। अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन तक पहुंचाने का दम भरती रही, इसके लिए कुछ समितियां भी गठित की गईं। फिर भवन निर्माण जैसे जिन कुछ क्षेत्रों में सुस्ती बनी हुई थी, उसे तोड़ने के लिए अपनी तरफ से भारी निवेश जुटाने की घोषणा कर दी। जबकि समग्र विकास नीति पर पुनर्विचार की जरूरत थी। अब जब आर्थिक विकास दर सिमट कर साढ़े चार फीसद पर पहुंच गई है और महंगाई पर काबू पाना कठिन हो गया है, तो नए तरीके से कर लगाने के प्रयास हो रहे हैं। कुछ उद्यमों को उत्पादन के क्षेत्र से निकाल कर बाहर कर दिया गया है, ताकि उन पर अठारह के बजाय बाईस फीसद जीएसटी वसूला जा सके। जाहिर है, इससे उन क्षेत्रों के कारोबार पर असर पड़ेगा और कर वसूली का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह कर बढ़ा कर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना संभव नहीं होगा।

रिजर्व बैंक अपनी दरों में कटौती इसलिए करता है कि बाजार में पूंजी का प्रवाह और उद्योग-धंधों में निवेश बढ़े। पर जब वह अपने हाथ रोके रखता है, तो उसका अर्थ होता है कि उसे जल्दी ही अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद नहीं है। यानी बैंकों का ऋण कारोबार पहले ही धीमा चल रहा था, रेपो दरों में कटौती न होने से उसमें कुछ तेजी आने की उम्मीद भी धुंधली हो गई है। बैंकों का कारोबार मंद होने का अर्थ है कि उत्पादन, विपणन, विनिर्माण आदि सभी क्षेत्रों के प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ता है। पहले ही प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करना सरकार के लिए मुश्किल बना हुआ है और वाहन उद्योग, कपड़ा उद्योग जैसे क्षेत्रों पर मंदी की बुरी मार पड़ी है। उस पर विकास दर की रफ्तार धीमी होने से बाहरी निवेश आने की उम्मीद और क्षीण हो गई है। इस तरह रोजगार सृजन के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खुलना भी मुश्किल है। इस स्थिति से पार पाने के लिए सरकार को व्यावहारिक उपायों पर विचार करना होगा।

बुजुर्गों की फिक्र

समाज में बुजुर्गों के जीवन में मुश्किलों को कम करने के मकसद से लंबे समय से कवायदें चल रही हैं, लेकिन आज भी वे व्यावहारिक स्वरूप नहीं ले सकी हैं। इस मामले में समय-समय पर कई तरह के कानूनी प्रावधान किए गए, जिनके तहत बेटे-बेटियों से लेकर दूसरे संबंधों की भी जिम्मेदारियां तय की गई हैं। लेकिन आमतौर पर व्यवहार में उनके पालन को लेकर कई जगह लापरवाही देखी जाती है। इसके अलावा, कुछ सामाजिक संबंध ऐसे भी हैं, जो खुद को मौजूदा कानूनी प्रावधानों के दायरे से बाहर मानते हैं। हालांकि अब इस दिशा में भी कानूनों का विस्तार करने की कोशिशें जारी हैं, ताकि बुजुर्गों के आसपास मौजूद लोगों की भूमिकाएं कानूनी तौर पर निर्धारित की जा सकें। इस मकसद से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण (संशोधन) अधिनियम, 2019 को मंजूरी दी है, जिसके तहत बुजुर्ग सास-ससुर की देखभाल करने में नाकाम रहने और मासिक गुजारा खर्च नहीं मुहैया कराने पर दामाद और बहू के खिलाफ भी मुकदमा चलाए जा सकने के प्रावधान किए गए हैं।

कई बार देखा जाता है कि कुछ परिवारों में बुजुर्ग अपने घर के बच्चों के बड़े हो जाने या विवाह होने पर उनके दूसरी जगहों पर चले जाने या फिर एक परिवार के रूप में जीवन शुरू करने के बाद अकेले हो जाते हैं। लेकिन पुत्र के अपनी पत्नी के साथ परिवार से अलग हो जाने से इतर यह भी संभव है कि किसी माता-पिता को केवल पुत्री हो। ऐसे में कानून के तहत अगर सिर्फ पुत्र की भूमिका तय होती है, तब बाकी लोग अपनी जिम्मेदारी समझना जरूरी नहीं समझते। जबकि पुत्री और दामाद की भी यह जवाबदेही है कि वे जरूरी होने पर अपने माता-पिता का खयाल रखें। यह सामाजिक संबंधों में मानवीयता और संवेदना को कायम रखने के लिए एक स्वाभाविक तत्त्व भी होना चाहिए। लेकिन अगर कुछ लोग इन संवेदनाओं का निर्वाह नहीं करते हैं, तो इसके लिए कानूनी व्यवस्था की पहलकदमी स्वागतयोग्य है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि जीवन की सांध्यबेला में भी बुजुर्गों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आर्थिक के साथ-साथ मानसिक सहयोग की भी जरूरत होती है।

वक्त के साथ समाज का स्वरूप बदलना एक हद तक स्वाभाविक कहा जा सकता है। लेकिन समाज के घटक एक-दूसरे के साथ कुछ संवेदनाओं से जुड़े होते हैं। लेकिन इन संवेदनाओं की बुनियाद पर खड़े समाज में अमूमन हर व्यक्ति की कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। यह समाज खुद भी विकसित करता है और इसे शासन की ओर से भी निर्धारित किया जाता है। हमारे समाज के मुख्य घटक परिवार के ढांचे में लगभग सभी पीढ़ियों की भूमिकाएं तय मानी जाती हैं। माता-पिता से उम्मीद की जाती है कि वे जिन्हें जन्म देते हैं, आत्मनिर्भर होने तक उनका खयाल रखें। फिर बच्चों से भी यह उम्मीद होती है कि अपने दम पर खड़े होने के बाद वे अपने माता-पिता, अभिभावक या फिर घर के बुजुर्गों के लिए हर वह काम करें, जिनकी उन्हें जरूरत पड़ती है। इसी तरह की जिम्मेदारियों का निर्वहन किसी परिवार की संरचना को सहयोगात्मक, संपूर्ण, सेहतमंद बनाए रखता है और समाज को एक ठोस शक्ल देता है। जबकि इसकी कड़ियों के ढीला होने पर समाज के सूत्र कमजोर होते हैं और इस तरह एक व्यापक बिखराव की जमीन बनती है, जिसका खमियाजा न केवल बुजुर्गों, बल्कि बाद की पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ता है।

कल्पमेधा

प्रकृति अपनी प्रगति और विकास में रुकना नहीं जानती। हर अकर्मण्यता पर वह अपने शाप की छाप लगाती जाती है।

-गेटे

ईरान में प्रदर्शन और भारत की चिंताएं

सुजाता माथुर

निश्चित रूप से भारत अपने व्यापारिक और अंतरराष्ट्रीय राजनयिक संबंधों को सिर्फ अमेरिकी चश्मे से नहीं देख सकता। हमें यह तो समझना ही होगा कि हम इसकी क्या कीमत चुका रहे हैं और इसकी भरपाई कैसे करेंगे।

बीते मंगलवार को एमनेस्टी इंटरनेशनल से मिली एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान में अब तक दो सौ आठ प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। एमनेस्टी के एक अधिकारी के अनुसार इनमें से ज्यादातर मौतें पिछले एक सप्ताह में प्रदर्शनों को रोकने के लिए की गई सरकारी कार्रवाई के दौरान हुई हैं।

ईरान में पिछले 15 नवंबर से वहां की सरकार द्वारा तेल की कीमतें बढ़ाए जाने के विरोध में जबर्दस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार इनसे निपटने के लिए पुलिस बल का सहारा ले रही है। उसने इंटरनेट पर भी पाबंदी लगा दी है। इसलिए देश के भीतर क्या हो रहा है, इसकी सही-सही जानकारी बाहर नहीं आ पा रही है। ईरान की संवाद समितियां आईआरआईबी और इरना पूरी तरह चुप हैं और वहां के अखबारों में इन प्रदर्शनों के बारे में खबरें नहीं छप रही हैं। लेकिन इधर-उधर से छन कर आ रही खबरों के अनुसार इन प्रदर्शनों ने वहां काफी उग्र रूप धारण कर लिया है। एमनेस्टी की रिपोर्ट इसका एक संकेत है।

ईरान में इसकी भूमिका कैसे तैयार हुई, यह विस्तृत अध्ययन का विषय है, लेकिन असंतोष का तात्कालिक कारण ईंधन के संबंध में लागू किए गए वहां की सरकार के नए नियम ही हैं। नए नियम के अनुसार अब प्रत्येक मोटर मालिक को प्रतिमाह सिर्फ साठ लीटर पेट्रोल पंद्रह हजार रियाल प्रति लीटर की दर से मिलेगा। अगर वह इससे अधिक पेट्रोल खरीदता है तो उसे प्रति लीटर तीस हजार रियाल का भुगतान करना होगा।

इससे पहले मोटर मालिकों को दस हजार रियाल प्रति लीटर की दर से एक माह में ढाई सौ लीटर पेट्रोल खरीदने की अनुमति थी। जब तेल नियम में किए गए बदलावों के खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुए तब ईरान सरकार के हवाले से जारी एक रिपोर्ट में बताया गया था कि नए नियम के तहत पेट्रोल पर लागू सब्सिडी हटाने से उसे जो धन प्राप्त होगा उससे देश के निम्न आयवर्ग के लोगों को नकद लाभ दिया जाएगा। बताया गया था कि इससे सरकार को प्रतिवर्ष तीन सौ ट्रिलियन रियाल की आय होगी और इस धन से जल्दी ही करीब अठारह मिलियन परिवारों को अतिरिक्त नगद भत्ता देना शुरू कर दिया जाएगा।

सरकार द्वारा मुहैया सब्सिडी के कारण ईरान में शेष विश्व के मुकाबले तेल की कीमत सबसे कम है। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरानी तेल निर्यात में बेहद गिरावट आई है और उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। ऐसे में ईरान सरकार अपने घरेलू उपभोग पर सब्सिडी की कटौती कर रही है, ताकि कमजोर आयवर्ग के लोगों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को वह जारी रख सके।

तेल की कीमतों में की गई इस वृद्धि के विरोध में शुरू हुए आंदोलन से कुछ ही दिन पहले भारत की महिला पत्रकारों का एक दल ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ से मिला था। उनसे अपनी बातचीत में जरीफ ने इस बात की पुष्टि की थी कि अमेरिकी प्रतिबंध के कारण तेल से प्राप्त होने वाला राजस्व गिरा और मुद्रास्फीति बढ़ी है। उन्होंने कहा कि लेकिन ईरान की अर्थव्यवस्था का आधार तेल है, इसलिए वह तेल बेचता रहेगा और बहुत से देश उससे तेल खरीदते भी रहेंगे। लेकिन उस व्यापार में भ्रष्टाचार पनपेगा और संभव है कि पारदर्शिता भी न रहे।

जरीफ ने कहा कि इन प्रतिबंधों के चलते बहुत से देशों ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया है। हम समझते हैं कि कोई भी देश अमेरिका के खिलाफ जाकर अपना अहित नहीं करना चाहता, लेकिन उनके देश को इस बात से काफी तकलीफ हुई है कि भारत जैसे बड़े लोकतंत्र और दुनिया में तेल के तीसरे नंबर के सबसे बड़े उपभोक्ता ने भी अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए हैं और ईरान से तेल का आयात बंद कर दिया है। ईरान को लगता है कि भारत जैसे बड़े देश को अमेरिकी दादागीरी के सामने झुकना नहीं चाहिए था।

जरीफ ने कहा कि दरअसल, इससे दोनों देशों का अहित होगा। आप हमारा तेल नहीं खरीदेंगे तो हम आपका चावल, मसाले, चाय और अन्य रासायनिक उत्पाद नहीं खरीदेंगे। फिलहाल अपने परंपरागत सांस्कृतिक और राजनीतिक रिश्ते को शायद हम कुछ समय तक और बचाए रख सकें।

ईरान भारत का दूरस्थ पड़ोसी है और उसके साथ हमारा लंबा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ता रहा है। इसके अलावा चार अन्य ऐसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जिनमें ईरान के साथ भारत का गहरा संबंध रहा है। उसमें पहला है ऊर्जा का क्षेत्र। कच्चे तेल

और गैस के लिए यानी अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए हम जिन चार-पांच मुख्य देशों पर निर्भर हैं, उनमें ईरान का दूसरा स्थान है। हमारी ऊर्जा की साठ प्रतिशत जरूरतें ईरान और इस क्षेत्र के अन्य देशों से पूरी होती हैं। ईरान हमें प्रतिदिन चार लाख पचीस हजार बैरल तेल की आपूर्ति करता रहा है और उसके बदले में भारत उसके तेल और गैस उद्योग में निवेश करने वाले देशों में शामिल हैं।

दूसरा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है कनेक्टिविटी यानी संपर्क या पारगमन सुविधा। ईरान के रास्ते हमें अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे कई मुल्कों तक व्यापार संपर्क बढ़ाने की सुविधा मिली है। अफगानिस्तान, खासतौर से चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ देश है और पाकिस्तान के कारण हमारी उस तक पहुंच नहीं बन पाती, लेकिन ईरान के जरिए हम ऐसा कर सके हैं। ईरान स्थित चाबहार बंदरगाह के रास्ते हमारा व्यापार सिर्फ इन्हीं देशों तक नहीं, बल्कि पश्चिमी देशों के साथ भी संभव हो सका है। हालांकि अभी चाबहार बंदरगाह में भारत द्वारा निर्मित शहीद बहिश्ती टर्मिनल का परिचालन पूरी तरह शुरू नहीं हो सका है, लेकिन इसकी शुरुआत से सिर्फ नौ-दस माह में ही उसके जरिए हम दो लाख टन से ज्यादा कार्गो अन्य देशों तक भेज चुके हैं।

तीसरा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध, जिनकी शुरुआत 1950 से ही हो गई थी, हालांकि उस समय गुटनिरपेक्ष भारत सोवियत संघ के प्रभाव में था और ईरान अमेरिका के, लेकिन उनके बीच रिश्तों में कभी दरार नहीं आई। 1990 में दोनों ही देशों ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ नार्दर्न एलायंस की अशरफ गनी सरकार का समर्थन किया। विदेश नीति संबंधी इन मसलों पर जहां इन दोनों देशों का रवैया लगभग समान रहा, वहीं कुछ मामलों में उसमें विभेद भी रहा। भारत ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम का जोरदार विरोध किया और अफगानिस्तान में जहां दोनों ने तालिबान का विरोध किया, वहीं भारत ने वहां नाटो बलों की मौजूदगी का समर्थन किया।

चौथा क्षेत्र है ईरान में सिख धर्म के अनुयाइयों की उपस्थिति। ईरान में 2011 की जनगणना के हिसाब से सिखों के साठ परिवार रहते हैं। ये लोग वहां भारत के विभाजन से भी पहले से रहते आए हैं। इन परिवारों को वहां की इस्लामी सरकार ने गुरद्वारा बनाने और अपना धर्म मानने की इजाजत दी है। इस साल श्रीगुरुनानक देव जी की साढ़े पांच सौवीं जयंती पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये सिख परिवार वहां मुख्य रूप से व्यवसाय करते हैं और उनके बच्चे वहां के भारतीय स्कूल में अन्य विषयों के साथ-साथ फारसी भाषा का भी अध्ययन करते हैं।

निश्चित रूप से भारत अपने व्यापारिक और अंतरराष्ट्रीय राजनयिक संबंधों को सिर्फ अमेरिकी चश्मे से नहीं देख सकता। हमें यह तो समझना ही होगा कि हम इसकी क्या कीमत चुका रहे हैं और इसकी भरपाई कैसे करेंगे। जहां तक ईरान के भीतर उग्र होते जा रहे प्रदर्शनों का संबंध है, अगर उसके पीछे भी कुछ विदेशी ताकतों का हाथ हो तो आश्चर्य नहीं। अफगानिस्तान, सीरिया जैसे देशों के घरेलू आंदोलनों को दूसरे देशों ने ही हवा दी थी।

नेपथ्य के नायक

राजेंद्र वामन काटदरे

दुनिया मेरे आगे

हमारे देश को ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता मिली तो इसका श्रेय मुख्य रूप से महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल आदि के साथ भगतसिंह, राजगुरु जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को दिया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन महान लोगों की बहुत भूमिका रही देश को आजाद कराने में, लेकिन इनके अलावा भी सैकड़ों-हजारों और भी थे, जिन्होंने अपने घर-परिवार की चिंता छोड़ कर इस महासंग्राम में आहुतियां दी थीं। इस महासंग्राम में कुछ लोगों ने विदेशी सामान का बहिष्कार करते हुए अपनी खून-पसीने की कमाई से खरीदे विदेशी कपड़े और सामान जला दिया। क्रांतिकारियों की चिट्ठियां एक से दूसरे के पास पहुंचाने का काम भी अनेक लोगों ने किया। इसी तरह अपने घरों में क्रांतिकारियों को पनाह देने वाले भी बहुत थे। कहा जा सकता है कि उस दौर में बहुत सारे लोगों ने सीधे तो आंदोलनों में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उन्होंने आंदोलन के दौरान जो भूमिकाएं निभाई थीं, उन्हें भले दर्ज नहीं किया गया, लेकिन उनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। दरअसल, 'अनसंग हीरोज' या फिर नेपथ्य के नायक इन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि इनके बलिदानों को इतिहास में कहीं कोई स्थान नहीं मिल पाया।

ये नायक सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम के वक्त नहीं थे, बल्कि वे आज भी हमारे आसपास मौजूद होते हैं, लेकिन हम उनके दखल पर गौर करने को तैयार नहीं होते। एक सत्य घटना का उल्लेख कर रहा हूं। उस दिन पुष्य नक्षत्र था, इसलिए शहर की आभूषण बेचने वाली तमाम दुकानों के विज्ञापनों से अखबार पटे हुए थे। इसकी वजह यह थी कि पुष्य नक्षत्र में सोना-चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। मेरे दो रिश्तेदार भी कुछ गहने खरीदने शाम को बाजार गए। बाजार में अन्य खरीदारी के बाद उन्होंने अपनी पसंद का गहना खरीदा तब तक अंधेरा छा चुका था। हमारा घर जहां है, वहां पहुंचने के लिए रास्ता कुछ दूर तक सुनसान है। इसलिए वे लूटपाट या झपटमारी की कुछ चिंता के साथ ही स्कूटर पर घर की ओर चले। तभी पीछे से हॉर्न बजाते मोटरसाइकिल पर दो लड़के तेजी से उनकी ओर आते नजर आए। वे हाथ से इशारे भी कर रहे थे। ऐसे में मेरे उन रिश्तेदारों का डर जाना स्वाभाविक ही था। इसलिए उन्होंने अपना स्कूटर रोकने के बजाय उसक गति बढ़ा दी। लेकिन अगले कुछ ही पलों में मोटरसाइकिल पर सवार युवक उनसे आगे निकल गए और एक जगह पर उन्हें रोक लिया। मेरे रिश्तेदार कई तरह की आशंकाओं से घिर गए थे कि इस बीच मोटरसाइकिल से उतर कर एक लड़का उनके पास आया और बोला कि 'अंकल, हम कब से आपको रुकने के लिए इशारा कर रहे हैं, लेकिन आप रुके ही नहीं। ये देखिए आंटी जी का बैग पीछे गिर गया था। वही देने के लिए हम आपको रुकने का इशारा कर रहे थे।' डरे हुए मेरे रिश्तेदारों के लिए यह बिल्कुल अप्रत्याशित और उम्मीदों से परे था। उनकी बातें सुन कर पहले तो दोनों की जान में जान आई और वे उन लड़कों को बहुत धन्यवाद देकर घर आ गए। घर आकर देखा तो गहने और सभी कीमती चीजें बैग में सही-सलामत थीं।

अखबारों में हम चोर-लुटेरों, भ्रष्ट नेताओं, व्यसनी-छली और तथाकथित संतों के समाचार और उनकी तस्वीरें रोज ही देखते रहते हैं, मगर उन मोटरसाइकिल सवार युवकों की तरह के तमाम नायक गुमनाम ही रह जाते हैं। जबकि हमारे समाज में लोगों के सभ्य और संवेदनशील होने की उम्मीद ऐसे ही लोगों से बची रहती है।

इस तरह की यह अकेली घटना नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कई गुमनाम नायक हमारे आसपास दिख जाते हैं, जिन पर हम ध्यान नहीं देते। किसी बुजुर्ग या महिला को बस में खड़ा देख कर तुरंत उठ कर वे अपनी सीट देते हैं। किसी स्टेशन पर दो मिनट के लिए रुकी ट्रेन से उतरते किसी बुजुर्ग का सामान उतार देने वाले या नए शहर में किसी पता पूछने वाले को सही पता बता कर ऑटो या बस में चढ़ने में मदद करने वाले वे गुमनाम नायक ही तो होते हैं, जिनसे समाज का मानवीय चेहरा बचा रहता है!

इतना ही नहीं, सड़क दुर्घटना में घायल किसी अनजान को अस्पताल पहुंचाने वाले या किसी अनजान को रक्तदान करने वाले, मरने के बाद ही सही, अपनी देह दान करने वाले सभी गुमनाम नायक ही हैं। मदद छोटी हो या बड़ी, मदद या सहयोग ये 'अनसंग हीरोज' बिना किसी निहित स्वार्थ के करते रहते हैं। इन्हें कई बार सिर्फ एक 'शुक्रिया' मिल जाता है तो कभी नहीं भी। लेकिन सच यह है कि इनके भीतर किसी भी तरह की अपेक्षा नहीं होती है। बस अपने मानवीय स्वभाव और संवेदनशीलता की वजह से तुरंत आगे बढ़ कर अपनी सीमा में जितना हो पाता है, उतना किसी अनजान के लिए भी बिना कुछ सोचे-समझे कर डालते हैं। बेशक ये तहेदिल से 'शुक्रिया' कहे जाने लायक हमारे नेपथ्य के नायक हैं।

हताशा में रक्षक

फिर एक हृदयविदारक घटना सामने आई जिसमें छत्तीसगढ़ के धुर नक्सल प्रभावित जिले में तैनात आइटीबीपी के एक जवान ने अपने चार सहकर्मियों की गोली मार कर हत्या कर दी। हाल ही में सुरक्षा बलों से संबंधित ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिनमें विभिन्न कारणों से सैनिकों ने अपने साथियों या वरिष्ठ अधिकारियों की हत्या कर दी। ऐसी घटनाओं के पीछे के वास्तविक कारणों की जांच अभी जारी है पर इन घटनाओं को सुरक्षा बलों के जवानों में विभिन्न कारणों से व्याप्त अवसाद, तनाव व कुंठा की चरम परिणति के रूप में माना जा सकता है। अक्सर सैनिकों की कई तरह की समस्याएं प्रकाश में आई हैं। आवश्यकता होने पर भी उन्हें अवकाश न मिलना सबसे आम समस्या है। हाल में सुकमा में नक्सल हमले में शहीद हुए जवान के संबंध में एक हैरान करने वाला तथ्य सामने आया कि उस हमले के कुछ ही दिन पूर्व एक अन्य हमले में वह दृढ़ता से लड़ते हुए जांघ में गोली लगने से घायल हो गया था। कुछ दिन के उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी होते ही उसे सीधे मोर्चे पर तैनात कर दिया गया। उसके शारीरिक स्वास्थ्य के आधार पर मांगे गए अवकाश के निवेदन को उच्चाधिकारियों ने स्वीकार नहीं किया था। वह जवान फिर भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटा और देश के लिए प्राण दे दिए।

खाने-पीने की सामग्री की गुणवत्ता और उसकी आपूर्ति में अनियमितता के संदर्भ में भी सैनिकों की शिकायतें आती रही हैं। विडंबना है कि ऐसे विभिन्न मामलों में आरोपी अथवा संस्था ही जांचकर्ता और न्यायाधीश की भूमिका में आ जाते हैं। निजी कारणों अथवा अनुशासन के नाम पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कनिष्ठ कर्मचारी-अधिकारियों को प्रताड़ित करने के चलते आत्महत्या की घटनाएं भी सामने आई हैं जो बहुत दुखद व चिंतनीय हैं। ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। सैनिकों की तरफ से आ रही व्यावहारिक दिक्कतों से जुड़ी शिकायतों का शीघ्रता से समुचित संज्ञान लिया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच तटस्थ व निष्पक्ष संस्था द्वारा उच्च न्यायालय की देखरेख में की जानी चाहिए। जवानों की वेतन संबंधी विसंगतियों को भी दूर करने की आवश्यकता है। उनका मनोबल बढ़ाने व धैर्य में वृद्धि के लिए अधिकारियों के लिए समय-समय पर सेमिनार का आयोजन किया जाना चाहिए। सैन्य बलों के प्रत्येक ठिकाने में एक मनोचिकित्सक की नियुक्ति भी की जानी चाहिए जो सलाहकार की भूमिका में सैनिकों को किसी भी प्रकार के अवसाद की स्थिति से बाहर आने में सहायक होंगे।

ये सैनिक ही हैं जिनकी बदौलत देश के आम नागरिक खुद सुरक्षित महसूस करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाते हैं। सैनिकों के बेहतर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बिना देश की सुरक्षा व प्रगति की कल्पना नहीं की जा सकती। लिहाजा, सरकारों को सैनिक कल्याण पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

● *ऋषभ देव पांडेय, पामगढ़, छत्तीसगढ़*

न्याय का तकाजा

सन 2013 में निर्भया प्रकरण से हाल तक महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों में केवल एक अंतर आया है और वह है अपराध की प्रकृति या किरदार का। निर्भया मामले के बाद जिस तरह के न्याय की आशा की गई थी वैसा देखने को नहीं मिला, क्योंकि अभी तक निर्भया के मुजरिमों को सजा नहीं मिली। अगर हम ऐसे संगीन मामलों में दंड देने की नजीर पेश नहीं करेंगे तो अपराधियों का हौसला बढ़ता रहेगा। कानून बनाने तक ही हमारी जिम्मेदारी सीमित नहीं है, इससे आगे हमारी जवाबदेही इसे लागू कराने की भी है। हमें आज के बारे में सोच कर आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर समाज का निर्माण करना होगा जिसकी पहचान एक सभ्य समाज के रूप हो।

● *गौरव मिश्रा, इलाहाबाद*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

प्याज के आंसू

देश के कई राज्यों में लोग प्याज के आंसू रो रहे हैं। प्याज कई शहरों में 75 से 100 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है। इस पर सियासत भी खूब की जा रही है। कभी किसी नेता के बयान को 'ट्रोल' किया जा रहा है, तो कभी सांसद प्याज की माला लेकर संसद में आ जाते हैं। इस बीच तुर्की से 4000 टन प्याज आयात करने की खबर आ रही है, जो कि मध्य जनवरी तक भारत पहुंच जाएगा। इसके अलावा भी भारी मात्रा में मिस्र से प्याज का आयात किया जाएगा।

गौरतलब है कि हमारे देश के ही महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात व बिहार समेत कई राज्यों में प्याज की भरपूर पैदावार होती है। सरकारी गोदामों में रखे प्याज के हर साल सड़ जाने या खराब हो जाने की खबरें भी आती हैं। इसके बावजूद हमें विदेशों से प्याज आयात करना पड़ रहा है! सरकार को चाहिए कि सरकारी गोदामों में सामान के रख-रखाव की स्थिति में सुधार लाए और कालाबाजारी पर रोक लगाने के प्रयास करे। यदि अपने देश के किसानों से खरीद कर सही तरह से प्याज का रखरखाव किया जाता तो आज हमें उसका आयात करने की जरूरत नहीं पड़ती।

● *उपासना, दिल्ली विश्वविद्यालय*

कानून के मुताबिक

सांसद और विधायक सिर्फ जनप्रतिनिधि नहीं होते। वे नियम बनाने और देश चलाने वाले भी होते हैं। इसलिए उन्हें हर वक्तव्य काफी सोच-समझ कर देना चाहिए। अब राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने सोमवार को संसद में कह दिया कि जिन्होंने हैदराबाद की पशु चिकित्सक के साथ बलात्कार कर उसे जला दिया, उनकी 'मॉब लिंचिंग' कर दी जानी चाहिए। ठीक है, जयाजी काफी क्रोधित थीं इसलिए ऐसा कह दिया होगा। मगर उन्हें आम आदमी जैसा बयान देने से बचना चाहिए था। क्या उन्हें नहीं मालूम कि यह देश कानून और संविधान के प्रावधानों से चलता है। ऐसे में अजमल कसाब को भी तुरंत मार देना चाहिए था। मगर ऐसा नहीं किया गया।

हमारा समाज सऊदी अरब नहीं है। हां, कानूनी प्रक्रिया में देर क्यों होती है, इस देरी को कैसे खत्म किया जाए, इस पर सांसदों को मंथन करना चाहिए। वैसे केवल कानून कड़ा कर देने और मोमबत्ती वाले प्रदर्शनों से पुरुषों की हैवानियत नहीं रुकने वाली। सदियों से यह होता आया है। शिक्षा और संपन्नता के विस्तार से भी ये नहीं रुकने वाला है। अगर ऐसा होता तो फिर यूरोप और अमेरिका में बलात्कार कब का खत्म हो गया होता।

● *जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर*

www.readwhere.com